

प्रेषक,

आलोक कुमार वर्मा,  
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,  
मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,  
नैनीताल।

न्याय अनुभाग—1

देहरादून: दिनांक 18 दिसम्बर, 2017

**विषय—** मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के अधिष्ठान में कार्यरत वाहन चालकों एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को छाता उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के पत्र सं०-4245/UHC-2017/Management दिनांक 03.10.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल के अधिष्ठान में कार्यरत वाहन चालकों एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के लिए छाता क्रय करने हेतु धनराशि में वृद्धि का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है।

2— इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल के अधिष्ठान में कार्यरत वाहन चालकों एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को पूर्व अनुमन्य छाता सुविधा सम्बन्धी शासनादेश सं०-2740/VII-1-10/17-उद्योग/2004 दिनांक 12.01.2011 में नियत दर रु० 110/- प्रति छाता के स्थान पर रु० 270/- प्रति छाता अनुमन्य किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

3— उक्त पर होने वाला व्यय आय व्ययक के अनुदान सं०-04 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक “2014—न्याय प्रशासन—00—आयोजनेत्तर—102—उच्च न्यायालय—03—उच्च न्यायालय—08—कार्यालय व्यय” के नामे डाला जायेगा।

4— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं०-07 भरित/XXVII(5)/2017 दिनांक 18.12.2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(आलोक कुमार वर्मा)  
प्रमुख सचिव

संख्या—366 (।) /XXXVI(1)/2017-316/2017 तददिनांकित।

**प्रतिलिपि—** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2— वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
- 3— वित्त अनुभाग—5/एन०आई०सी०/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महेश चन्द्र कौशिवा)  
अपर सचिव